अपर मुख्य सचिव, नियोजन की अध्यक्षता में एस0डी0जी0 इण्डिया इंडेक्स-2.0 (2019-20) व इंडेक्स-3.0 (ड्राफ्ट रिपोर्ट), एस0डी0जी0 के लोकेलाइजेसन तथा एस0आई0एफ0 एवं डी0आई0एफ0 आदि के सम्बन्ध में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से दिनाँक 08.12.2020 के पूर्वान्ह 10:30 बजे, कक्ष सं0-111, योजना भवन, लखनऊ में सलाहकार, नीति आयोग, भारत सरकार एवं एस0डी0जी0 के नोडल विभागों के साथ आहूत बैठक / कार्यशाला का कार्यवृत्तः-

उपस्थित अधिकारियों का विवरण संलग्न है।

बैठक / कार्यशाला का शुभारम्भ करते हुए प्रमुख सचिव, नियोजन ने सुश्री संयुक्ता समद्दार, सलाहकार, नीति आयोग एवं उनके प्रतिनिधि मण्डल तथा बैठक / कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाले नोडल विभागों एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों का स्वागत करते हुए प्रदेश में एस0डी0जी0 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति से अवगत कराया।

प्रमुख सचिव, नियोजन द्वारा बताया गया कि नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा दिसम्बर, 2018 में एस0डी0जी0 इण्डिया इंडेक्स-1.0 तथा दिसम्बर, 2019 में एस0डी0जी0 इण्डिया इंडेक्स-2.0 जारी किया गया था। इंडेक्स-1.0 के सापेक्ष इंडेक्स-2.0 में उत्तर प्रदेश द्वारा किये गये बेहतर प्रदर्शन के फलस्वरूप, प्रदेश "फास्टेस्ट मूवर्स स्टेट" की श्रेणी में आया था। आशा है कि आगामी एस0डी0जी0 इण्डिया इण्डेक्स-3.0 में भी प्रदेश बेहतर प्रदर्शन करेगा। एस0डी0जी0 के क्रियान्वयन हेतु विगत दो-तीन वर्षों में प्रदेश द्वारा विभिन्न सेक्टर्स में विभिन्न कार्य सम्पन्न किये गये हैं, परन्तु नीति आयोग द्वारा निर्गत विभिन्न इंडेक्सेस में सम्मिलित अधिकांश इंडीकेटर्स का डेटा लगभग 3-4 वर्षों से पूर्व का है। एस0डी0जी0 इण्डिया इण्डेक्स-3.0 (ड्राफ्ट रिपोर्ट) में प्रदेश से सम्बंधित प्रस्तावित 118 इंडिकेटर्स में से लगभग 60 से अधिक इंडीकेटर्स का डेटा वर्ष 2011-12 से वर्ष 2018-19 तक का है, जिसके कारण एस0डी0जी0 के परिप्रेक्ष्य में विगत 2-3 वर्षों में प्रदेश द्वारा की गयी प्रगति इन इंडेक्सेस में प्रदर्शित नहीं हो पा रही है।

इस सम्बन्ध में सुश्री संयुक्ता समद्दार, सलाहकार, नीति आयोग द्वारा अवगत कराया गया कि एस0डी0जी0 इण्डिया इण्डेक्स-2.0 (2019-20) में सामाजिक एवं मानव विकास क्षेत्रों से सम्बन्धित गोल सं0- 1 से 5, 10 एवं 13 को छोड़कर शेष अन्य 8 गोल्स में प्रदेश द्वारा बेहतर प्रदर्शन किया था। उत्तर प्रदेश द्वारा एस0डी0जी0 विज़न, टार्गेट मैपिंग, एस0आई0एफ0, डी0आई0एफ0 तथा एस0डी0जी0 सेल की स्थापना, एस0डी0जी0 पोर्टल / डैशबोर्ड, राज्य एवं जनपद स्तर पर एस0डी0जी0 के अनुश्रवण हेतु टास्क फोर्स / समितियों का गठन आदि कार्य सम्पन्न कर लिये गये हैं, जो कि सराहनीय है। उत्तर प्रदेश में गोलवाइज़ / स्कीमवाइज़ बजट

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

आवंटन के कार्य में अभी अपेक्षित प्रगति नहीं हो पायी है। कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं हरियाणा राज्यों द्वारा गोलवाइज़ / स्कीमवाइज़ बजट आवंटन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इन राज्यों में किये गये बजट आवंटन से सम्बन्धित कार्य प्रणाली का अध्ययन कर उत्तर प्रदेश द्वारा भी बजट आवंटन का कार्य सुगमता से किया जा सकता है।

सलाहकार, नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा आगामी एस0डी0जी0 इण्डिया इंडेक्स-3.0 के परिप्रेक्ष्य में अपेक्षा की गयी कि एस0डी0जी0 के सभी नोडल विभागों द्वारा अपने-अपने गोल से सम्बन्धित इंडीकेटर्स की इंडेक्स-3.0 की ड्राफ्ट रिपोर्ट में अंकित प्रगति के आँकड़ों की समीक्षा कर यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि इस रिपोर्ट में अंकित आँकड़े विभागीय आँकड़ों के समान हैं। इस ड्राफ्ट रिपोर्ट में अंकित आँकड़ों तथा प्रदेश की प्रगति के वास्तविक आँकड़ों में यदि कोई भिन्नता आती है तो उस स्थिति में वास्तविक आँकड़ों को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों आदि के पोर्टल / वेबसाइट पर सम्बन्धित मंत्रालयों / विभागों से समन्वय स्थापित कर अतिशीघ्र अपलोड / अपडेट करा दिये जायें, जिससे इन आँकड़ों को जनवरी, 2021 में जारी होने वाली एस0डी0जी0 इंडिया इंडेक्स-3.0 में सम्मिलित किया जा सके।

कतिपय नोडल विभागों द्वारा सलाहकार, नीति आयोग के संज्ञान में लाया गया कि इंडेक्स-3.0 की ड्राफ्ट रिपोर्ट में प्रस्तावित कई इंडीकेटर्स ऐसे हैं, जिनके आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं। अतः इन इंडीकेटर्स के प्रस्तावित स्कोर का विभाग द्वारा परीक्षण करना सम्भव नहीं हो पा रहा है। सलाहकार नीति आयोग द्वारा स्पष्ट किया गया कि इस प्रकार के इंडीकेटर्स के आँकड़ों को नोडल विभागों के अनुरोध पर नीति आयोग द्वारा उपलब्ध कराया जा सकता है। इंडीकेटर्स के आँकड़ों को अपलोड / अपडेट एवं डेटा उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी नोडल विभाग को यदि कोई कठिनाई आती है, तो इसके निराकरण हेतु सुश्री विद्या वारियर, एस0डी0जी0 यंग प्रोफेशनल, नीति आयोग (ई-मेलः vidya.warrier@nic.in एवं मो.- 09769824155) से सम्पर्क किया जा सकता है।

सलाहकार, नीति आयोग द्वारा एस0डी0जी0 इंडिया इंडेक्स-2.0 व इंडेक्स-3.0 की ड्राफ्ट रिपोर्ट पर गोलवाइज़ / इंडीकेटरवाइज़ चर्चा की गयी तथा इस सम्बन्ध में में नीति आयोग द्वारा नोडल विभागों के विभिन्न प्रश्नों / जिज्ञासाओं का समाधान किया गया। उक्त के साथ ही सलाहकार, नीति आयोग द्वारा एस0डी0जी0 लोकेलाइजेशन के सम्बन्ध में जनपद स्तर पर एस0डी0जी0 के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु एक सुदृढ़ व्यवस्था बनाये जाने पर बल दिया गया।

श्रीमती वारालिका दुबे, अधीक्षण अभियंता, ऊर्जा विभाग द्वारा अनुरोध किया गया कि सभी प्रदेशों द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये महत्वपूर्ण प्रयास

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

किये जा रहे हैं, परन्तु इससे सम्बन्धित कोई भी इंडीकेटर इंडेक्स-3.0 ड्राफ्ट रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं है।

श्री विजय किरन आनन्द, मिशन निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान द्वारा अनुरोध किया गया कि गोल सं0- 4 (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा) के इंडीकेटर क्रमांक- 4.1.4 (Average performance of class X students in Language and Maths in the NAS assessment) में कक्षा-10 के विद्यार्थियों को ही सम्मिलित किया गया है, जबकि नई शिक्षा नीति के दृष्टिगत इसमें कक्षा-3, 5 एवं 8 के विद्यार्थियों को भी सम्मिलित किये जाने के साथ ही इंडीकेटर क्रमाँक- 4.5.2, 4.C.1 एवं 4.C.(P) में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर को भी सम्मिलित किये जाने पर विचार किया जाना उचित होगा। उक्त अनुरोध पर सहमति व्यक्त करते हुए सलाहकार महोदया द्वारा नीति आयोग / मॉस्पी के शीर्ष अधिकारियों से विचार-विमर्श कर तद्नुसार अग्रतर कार्यवाही किये जाने का आश्वासन दिया गया।

सुश्री विशेष उप्पल, निदेशक, डब्लू.डब्लू.एफ. इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा जनपद पीलीभीत व मुरादाबाद के लिये तैयार की जा रही मॉडल जिला योजना के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण किया गया। इस प्रस्तुतीकरण को सभी जनपदों के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी तथा उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या के साथ साझा करने हेतु निर्देश दिये गये। जिला अर्थ एवं संख्याधिकारियों एवं उप निदेशकों से यह अपेक्षा की गयी कि उनके द्वारा उक्त मॉडल जिला योजना का अध्ययन कर इसे अन्तिम रूप दिये जाने हेतु सक्रिय भूमिका निभायी जाये।

प्रमुख सचिव, नियोजन द्वारा सलाहकार, नीति आयोग के संज्ञान में लाया गया कि इंडेक्स-3.0 की ड्राफ्ट रिपोर्ट में लगभग 50 प्रतिशत से अधिक इंडीकेटर्स ऐसे हैं, जिनके स्कोर में इंडेक्स-2.0 के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः सुझाव है कि नीति आयोग द्वारा एस0डी0जी0 इण्डिया इंडेक्स-3.0 का प्रकाशन दो खण्डों में इस प्रकार किया जाये कि खण्ड एक में ऐसे इंडीकेटर्स सम्मिलित किये जायें जिनके स्कोर में कोई परिवर्तन नहीं है तथा खण्ड दो में ऐसे इंडीकेटर्स सम्मिलित किये जायें जिनका डेटा नवीन एवं परिवर्तनीय है। उक्त सुझाव पर सलाहकार महोदया दवारा नीति आयोग में चर्चा /विचार-विमर्श करने की बात कही गयी।

सम्यक विचार-विमर्श के उपरान्त प्रमुख सचिव महोदय द्वारा निम्नांकित निर्देश दिये गयेः-

1- सभी नोडल विभागों द्वारा एस0डी0जी0 इण्डिया इंडेक्स-3.0 की ड्राफ्ट रिपोर्ट में अपने-अपने गोल से सम्बन्धित इंडीकेटर्स की प्रगति के आँकड़ों की तत्काल समीक्षा कर नीति आयोग की अपेक्षानुसार अद्यतन आँकड़े भारत सरकार के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

विभिन्न मंत्रालयों / विभागों आदि के पोर्टल / वेबसाइट पर एक सप्ताह के अन्दर यथा आवश्यतानुसार अपलोड कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(कार्यवाही- समस्त नोडल विभाग)

2- प्रत्येक नोडल विभाग द्वारा 18 दिसम्बर, 2020 से पूर्व नियोजन विभाग को इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाये कि उनके द्वारा अपने गोल से सम्बन्धित सभी इंडीकेटर्स की प्रगति के आँकड़े एवं डेटा सोर्स का सम्यक मिलान कर लिया गया है एवं इसमें अब किसी प्रकार संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

(कार्यवाही- समस्त नोडल विभाग)

3- प्रदेश के सभी जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी एवं उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या से अपेक्षा की गयी कि डब्लू.डब्लू.एफ. इण्डिया द्वारा जनपद पीलीभीत एवं मुरादाबाद हेतु तैयार की जा रही मॉडल जिला योजना (ड्राफ्ट) का अध्ययन कर इसे अन्तिम रूप दिये जाने हेतु सक्रिय भूमिका निभायी जाये।

(कार्यवाही- निदेशक, डब्लू.डब्लू.एफ. इण्डिया, नई दिल्ली / समस्त जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी / उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग)

अन्त में बैठक / कार्यशाला सधन्यवाद समाप्त हुई।

कुमार कमलेश
अपर मुख्य सचिव

दीर्घकालीन योजना प्रभाग,
राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0
कालाकांकर भवन, पुराना हैदराबाद, लखनऊ।

पत्रांकः 124/2020/769/35-1-2020 **दिनांकः16 दिसम्बर, 2020**

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- एस0डी0जी0 के समस्त नोडल / संबंधित विभागों के **अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/ सचिव-**

ग्राम्य विकास, खाद्य एवं रसद, कृषि, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, महिला कल्याण एवं बाल विकास पुष्टाहार, सिंचाई, पंचायतीराज, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, औद्योगिक विकास, समाज कल्याण, नगर विकास, पर्यावरण, वन, गृह, वित्त, श्रम एवं संस्थागत वित्त विभाग, उ0प्र0शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

3- प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

4- सुश्री संयुक्ता समद्दार, सलाहकार, नीति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।

5- समस्त जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी / जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी उ0प्र0।

6- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, नियोजन विभाग,उ0प्र0 शासन।

7- निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0।

8- श्रीमती पीयूष एंटोनी, विशेषज्ञ, सोशल पॉलिसी स्पेस्लिस्ट, यूनीसेफ, लखनऊ।

9- सुश्री विशेष उप्पल, निदेशक, डब्लू.डब्लू.एफ. इण्डिया, नई दिल्ली।

10- श्री रवि कुमार, यू0एन0डी0पी0।

(आर0एन0एस0 यादव)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।